DR. KARAN SINGH: Sir, the question of conservation, particularly, of tiger is a question that has been agitating the mind of the nation for many years. In fact, there is also mention in the President's Address this time. Now, the hon. Minister has said that they don't keep statistics of poaching in the sanctuaries. It is very strange because it is after all a Central project, Project Tiger. A vast sum of money is given by the Central Government. How could it be that the Central Government does not keep statistics on poaching and does not keep an eye on the poachers?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I said that we did not have such figures in reply to the earlier question as to how many officers are found helping in poaching. As far as poaching is concerned, we have got the figures. The figures are made available to us by the State Governments. I have the figures for the last three years with me and I can provide them to the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can send them to the hon. Member.

ग्वालियर-इटावा रेल लाइन का बिछाया जाना

*185. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्वालियर से इटावा (उ॰ प्र॰) तक रेल लाइन बिछाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ वेलू): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) गुना और इटावा (344 किलोमीटर) के बीच नई लाइन का कार्य 1985-86 के बजट में शामिल किया गया था। गुना-ग्वालियर-भिंड (306 किलोमीटर) के बीच कार्य पहले ही पूरा हो गया है और भिंड तथा इटावा खण्ड (38 किलोमीटर) के बीच प्रगति पर है। इस परियोजना के 2007-08 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

Laying of Gwalior-Etawah Rail Line

†*185. SHRI LAXMINARAYAN SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to lay railway line between Gwalior and Etawah (U.P.);

† Original notice of the question was received in Hindi.

(b) if so, by when the project is likely to be completed; and

(c) what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R. VELU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The work of new line between Guna and Etawah (344 kms.) was included in the Budget 1985-86. The work between Guna-Gwalior-Bhind (306 kms.) has already been completed and is in progress between Bhind and Etawah section (38 kms.). The project is likely to be completed during 2007-08.

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: उपसभापति जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि गुना से इटावा तक की रेलवे लाइन जो वर्ष 1985-86 से शुरू हुई थी, वह 2007-2008 में जाकर पूरी होगी। महोदय, ऐसा लगता है कि एक वर्ष में केवल 17 किलो मीटर की लाइन बन रही है, इसलिए 20 साल में भी यह पूरी नहीं हो पा रही है। इस तरह इस पर कितना डबल खर्च हो सकता है क्योंकि 20 साल में बहुत-सी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसको और जल्दी पूरा करने का प्रयास होगा? दूसरा सवाल यह है कि भिंड और इटावा के बीच रेलवे का एक बहुत बड़ा पुल आता है, क्या उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी?

SHRI R. VELU: Sir, I quite agree with the hon. Member that this was started in the year 1985-86. Now the hon. Member also knows that out of 344 kilometres, we have already completed 306 kilometres, only a portion of 38 kilometres is remaining that too between Bhind and Etawah. Actually, there are three major bridges. One is on the Yamuna river the second is on the Kunwari river and the third is on the Chambal river. The sub-structure of the bridge on the Chambal river is almost 50 per cent complete. What has been inhibiting the progress of that project is forest land involved in this. There is one Garial Wildlife Sanctuary. So forest clearance was required in which both Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Governments were involved. We required about 106 hectares of land; 82 hectares from Uttar Pradesh and the remaining from the Madhya Pradesh. In these cases, the Supreme Court held that wherever the forest wildlife land is required, you have to necessarily get the permission from the Supreme Court. Knowing that it was being delayed, on 14th November, 2003, we moved the Supreme Court with an inter-locutory application for granting of permission. The Supreme Court then referred the matter to the Central

Empowered Committee of the Government of India to go into this and make recommendations. Accordingly, the Committee has made recommendations and the Supreme Court has issued orders in December, 2005 saying that we have to necessarily pay Rs. 7.75 crores towards the conservation part of the wildlife sanctuary and secondly, the State Government has to assess the present net value of the land and intimate it to the Railways. Afterwards, the Railways will have to pay that value. We have already paid Rs. 7.75 crores for conservation part of it. Now the State Government has to intimate to the Railways the value of the land. Soon after that, we will definitely provide it. ...*(Interruptions)*.

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: उपसभापति महोदय, वन और पर्यावरण विभाग केन्द्र का ही विभाग है। यहां से अगर वर्षों तक इसकी अनुमति नहीं मिलती, तो आपको स्वयं भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राज्य की तरफ से किसी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई है। आप कृपया इसको देख लें।

SHRI R. VELU: The hon. Member must understand that after the UPA Government took charge, we have moved the Supreme Court for orders. You must put this question to somebody else who had been sleeping over this.

श्री उपसभापति: श्री प्यारे लाल खंडेलवाल जी। ...(व्यवधान)... आप सिर्फ इटावा पर ही क्वैश्चन पूछें। ...(व्यवधान)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: माननीय उपसभापति जी, जो प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर ठीक से नहीं आया। मैं वह प्रश्न फिर से पूछ रहा हूं। गुना-इटावा लाइन पर जो तीन बड़ी नदियाँ हैं, उनमें चम्बल, यमुना और क्वारी नदी है। ...(व्यवधान)... वह कावेरी नहीं है, क्वारी है। ...(व्यवधान)... कावेरी तो दक्षिण में है। ...(व्यवधान)... क्वारी नदी पर पुल बना है, लेकिन चम्बल का पुल अधूरा है। वहाँ पर न तो पर्यावरण का सवाल है और न ही वन विभाग का सवाल है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों नदियों के पुल कब तक पूरा हो जाएँगे? क्या आप उसका कोई समय निर्धारित करेंगे?

SHRI R. VELU: According to the information which my office has collected, the Yamuna bridge is complete upto sub-structure the Kunwari bridge is also complete up to sub-structure. So far as the Chambal river is concerned, 50 per cent of the bridge work has been completed. The hon. Member is saying that no forest land is required. How can he say that no forest land is required?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is saying that no forest clearance is required for that bridge.

SHRI R. VELU: Sir, that work is going on. But what about the land of the sanctuary on which we have to lay the line?

श्री उदय प्रताप सिंह: उपसभापति जी, मैं इटावा की ही बात पूछूंगा। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अभी मैं किसान पर भी पूछना चाहता था, क्योंकि मैं भी छोटा किसान हूँ।

श्री उपसभापति: आप यह क्या कह रहे हैं?

श्री उदय प्रताप सिंह:

जिन्होंने जान देकर मेकदे की आबरू रख ली।
वही एक-एक कतरे को तरसाये जाते हैं।
सर, यह तो ठीक नहीं है।

श्री उपसभापति: आप प्रश्न पूछिए।

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, मैं इसी पर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसा है कि यह लाइन गुना से इटावा नहीं है, बल्कि यह लाइन है ग्वालियर से इटावा, इटावा से मैनपुरी होते हुए एटा तक के लिए, जो पूरी पास हुई थी। मंत्री जी, आप बताएं कि यह बात सही है या नहीं? मंत्री जी, यह आपके जमाने में ही हुई थी। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर इस रफ्तार से लाइन बनेगी, तो इस तरह तो यह काम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि उधर से भी हो, क्योंकि वह एक बड़ा स्टेशन है, इटावा से लेकर एटा तक ऐसा सूना है कि एक आदमी भी कोई रेल का फायदा नहीं उठा पाता है। मेरा कहना यह है कि जब यह बना, सो बना, लेकिन इटावा से वही उसका हिस्सा है, उसको उधर से भी पूरा किया जाना चाहिए। क्या रेल मंत्री जी या सरकार इस पर विचार करेगी?

SHRI R. VELU: Sir, I fully understand the sentiment of the hon. Member. I only said, it would be completed by 2007-08. Maybe, we will hasten the process of completion. That is number one. Secondly, he is also asking for extension thereon from Etawah. In fact, that was examined ...*(Interruptions)*.

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, यह घोषित हो चुकी है, पैसा भी दिया जा चुका है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can provide any further information to the hon. Member.

श्रीमती माया सिंह: उपसभापति जी, यह जो गुना-इटावा के बीच में रेल लाइन का काम होना है, यह वर्ष 1985 में शुरू हुआ था, जब माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री थे। तो यह काम उस वक्त शुरू किया गया था और अब मंत्री जी का कहना है कि हम अभी आए हैं। मसला यह नहीं है कि एनडीए सरकार के समय में ...(व्यवधान)... सर, 20 साल, 21 साल से वहां की जनता बाट जोह रही है रेल की सीटी सुनने को, आवागमन के साधन की सुविधा पाने को, लेकिन यह काम अभी तक नहीं

हुआ है। इसमें जो तीन नदियां आती हैं, उसमें दो नदियों की बात नहीं, यह चंबल नदी पर तो थोड़ा सा काम बाकी है।

श्री उपसभापति: यह तो मंत्री जी बता चुके हैं। दूसरा कोई सवाल हो, तो पूछिए।

श्रीमती माया सिंह: सर, थोड़ा सा काम वहां का बाकी है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That information has already been given by the hon. Minister.

श्रीमती माया सिंह: सर, मैं जानना चाहती हूँ, जैसा मंत्री जी ने कहा, वे कह रहे हैं कि सैंक्चुरी के संरक्षण के लिए पैसे देना हैं, वहां की जमीन का मूल्य कितना है उसके लिए देखना है, यानी अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि जमीन का मूल्य कितना है, सैंक्चुरी के संरक्षण के लिए कितना पैसा देना है, तो फिर यह काम कैसे गति पकड़ेगा? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूं कि कब तक यह काम पूरा होगा?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He just wants to know when it is going to be completed.

SHRI R. VELU: Sir, it is not as if everything is pending. From Guna to Shivpuri, we have already opened 150 kms ...*(Interruptions)*... Why don't you listen patiently? We opened the traffic from Guna to Shivpuri in 1991 to the extent of 102 kms.; then, the work was completed to the extent of 125 kms. in 1999 from Shivpuri to Gwalior and to the extent of 79 dms. from Gwalior to Bhind in 2002. So, it is not that the work is not going on. Now for the balance of 38 km., since it covers the forest land, we have already remitted the money, that is, on 19.01.2006. The hon. Member wanted that the rest of the work should necessarily be undertaken. I would only request her to tell the State Government to value the land and let us know so that we can remit that money also and start the work. We will not delay it further. We may be able to complete the project and give you the line in full in 2007-08.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 186 ...*(Interruptions)*

श्रीमती माया सिंह: सर, राज्य सरकार का प्रपोजल मंत्री जी के पास आया है या नहीं आया है? यह मैं जानना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: इसके ऊपर बहुत हैं। ...(व्यवधान)... आपको अगर कहना है, तो हाफ एन आवर ...(व्यवधान)... Question No. 186।